2020 instead of continuing to so vest in the Central Government, shall vest in the Government company, subject to the following terms and conditions, namely:-

(1) the Government company shall make all payments in respect of compensation, interest, damages, etc. and the like, as determined under the provisions of the said Act and other relevant law;

(2) a Tribunal shall be constituted under section 14 of the said Act, for the purpose of determining the amounts payable by the Government company under condition (1) and all expenditure incurred in connection with any such Tribunal and persons appointed to assist the Tribunal shall be borne by the Government company and similarly, all expenditure incurred in respect of all legal proceedings like appeals, etc. for or in connection with the rights, in or over the said lands, so vested, shall also be borne by the Government company;

(3) the Government company shall indemnify the Central Government and its officials against any other expenditure that may be necessary in connection with any proceedings by or against the Central Government or its officials regarding the rights in or over the said lands so vested;

(4) the Government company shall have no power to transfer the aforesaid rights in the said lands so vested to any other person without the prior approval of the Central Government; and

(5) the Government company shall abide by such directions and conditions as may be given or imposed by the Central Government for particular areas of the said lands, as and when necessary.

[F. No. 43015/ 06/ 2019-LA&IR]

RAM SHIROMANI SAROJ, Dy. Secy.

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2021

का.आ. 113.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एंव निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 12, के उपनियम (2) के साथ पठित, निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एंव निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की शासकीय राजपत्र भाग-II, खण्ड-3, उप खण्ड (ii), में दिनांक 2 मई, 2019 की अधिसूचना सं. का.आ. 705, दिनांक 11 मई, 2020 को प्रकाशित अधिसूचना के स्थान पर, सिवाय उनके जो इस अधिक्रमण के पहले हो चुका है या होना है, मैसर्स मित्रा एस.के. प्राइवेट लिमिटेड, द्वार संख्या : 8-45-9/2/1, बी.सी विध्या नगर कॉलोनी, चौथी गली, निकट सी बी आई (ओल्ड) डाउन विशाखापट्नम - 530003 को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 1 मई, 2022 तक की अवधि के लिए-

क) खनिज और अयस्क – समूह 1, अर्थात, लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, फेरोमैंगनीज तथा बाक्साइट; और

ख) खनिज और अयस्क – समूह 2, अर्थात, क्रोम कंसन्ट्रेट सहित क्रोम अयस्क,

भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की शासकीय राजपत्र में प्रकाशित, दिनांक 20 दिसम्बर, 1965 की अधिसूचना सं॰ का.आ. 3975 तथा दिनांक 20 दिसम्बर, 1965 की अधिसूचना सं॰ का.आ. 3978 के तहत प्रकाशित अधिसूचना मे उपाबद्ध अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट क्रमश: उक्त खनिज और अयस्क का विशाखापट्नम पत्तन, गंगावरम पत्तन एवं काकीनादा पत्तन में निर्यात से पूर्व निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन एक अभिकरण के रुप में मान्यता देती है, अर्थात्:-

(i) यह अभिकरण, खनिज और अयस्क समूह-I के निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1965 तथा खनिज और अयस्क समूह-II के निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1965 के नियम 4 के अधीन निरीक्षण की पद्धति की

जाँच करने के लिये निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा निमित्त नामनिर्दिष्ट अधिकारियों को पर्याप्त सुविधाएं देगी; और

(ii) यह अभिकरण, इस अधिसूचना के अधीन अपने कार्यो के पालन में निदेशक (निरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण) निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा समय-समय पर, लिखित रूप में, दिए गए ऐसे निर्देशों से आबद्ध होंगी ।

[फा. सं. के-16014/3/2019-निर्यात निरीक्षण]

दिवाकर नाथ मिसरा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

New Delhi, the 11th February, 2021

S.O. 113.—In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), read with sub-rule (2) of rule 12 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry, number S. O. 705, dated the 2nd May, 2019, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub section (ii), dated the 11th May, 2019, except as respects things done or omitted to be done before such supersession,the Central Government hereby recognizes M/s Mitra S.K. Private Limited, Door no. 8-45-9/2/1/B, C Vidyanagar Colony, 4th Lane, Near Old CBI Down, Visakhapatnam- 530003, as an agency (hereinafter referred to as the said agency) for a period up to the 1st May, 2022, for inspection of-

(a) Minerals and Ores - Group I, namely the Iron Ore, Manganese Ore, Ferromanganese and Bauxite; and

(b) Minerals and Ores - Group II, namely the Chrome Ore including Chrome Concentrate,

as specified in the Schedule annexed to the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce, published in the Official Gazette *vide* number S.O. 3975 dated the 20th December, 1965, and S.O. 3978 dated the 20th December, 1965respectively, prior to export of the said Minerals and Ores at Visakhapatnam Port, Gangavaram Port and Kakinada Port, subject to the following conditions, namely: -

(i) the said agency shall give adequate facilities to the officers nominated by the Export Inspection Council in this behalf to carry out the inspection specified under rule 4 of the Export of Minerals and Ores - Group I (Inspection) Rules, 1965 and Export of Minerals and Ores - Group II (Inspection) Rules, 1965;

(ii) the said agency shall, in performance of its function as specified in this notification shall be bound by such directions, as the Director (Inspection and Quality Control), Export Inspection Council, may give in writing from time to time.

[F. No. K-16014/3/2019-Export Inspection]

DIWAKAR NATH MISRA, Jt. Secy.

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2021

का.आ. 114.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मै. उड़ीसा माइनिंग कोरपोरेशन के प्रबंधतंत्र, संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, भुवनेश्वर के पंचाट (संदर्भ सं. 04/2004) प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 03.02.2021 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-29011/43/2003-आईआर (एम)]

नवीन वैद्य, उप निदेशक